Gyanvividha, Vol.-3; Issue-2 (Apr.-June) 2026 : PP-389-395

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-6.125
Vol.-3; Issue-2 (Apr.-June) 2026
Page No.- 389-395
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. सुशील कुमार त्रिपाठी

अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश.

Corresponding Author :

डॉ. सुशील कुमार त्रिपाठी

अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश.

पश्चिम एशिया संघर्ष / संकट का वैश्विक प्रभाव (An Academic Study on the Global Impact of the West Asia Conflict/Crisis)

सार (Abstract) : फरवरी 2026 में इज़राइल-ईरान युद्ध के प्रारंभ के बाद पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गया है। गाज़ा में इज़राइल-हमास संघर्ष, लेबनान में इज़राइल-हिज़्बुल्लाह टकराव, यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाज़रानी पर हमले, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तेल परिवहन की रुकावट—इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक बहुआयामी क्षेत्रीय संकट को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि विश्व के हर महाद्वीप की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और कूटनीतिक संतुलन तक पहुँचा है। यह शोध पत्र पश्चिम एशिया संकट के प्रमुख आयामों—सैन्य, आर्थिक, मानवीय एवं भू-राजनीतिक—का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक तेल बाज़ार, मुद्रास्फीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों और विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। अध्ययन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD), संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों के आँकड़ों पर आधारित है।

मुख्य शब्द (Keywords) : पश्चिम एशिया, गाज़ा संघर्ष, इज़राइल-ईरान युद्ध, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, तेल संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानवीय संकट, भू-राजनीति।

1. प्रस्तावना : पश्चिम एशिया—जिसे मध्य पूर्व (Middle East) के नाम से भी जाना जाता है—विश्व के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र न केवल विश्व के तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार का एक बड़ा हिस्सा रखता है, बल्कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य, स्वेज़ नहर

और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का प्रवेश द्वार भी है। इस क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद ने अक्टूबर 2023 के बाद एक नया और अधिक विनाशकारी रूप धारण कर लिया, जो आगे चलकर लेबनान, यमन, इराक़ और अंततः ईरान तक फैल गया। फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर सैन्य हमलों के बाद यह संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में इतिहास का सबसे बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया।

इस शोध पत्र का उद्देश्य पश्चिम एशिया के वर्तमान संकट के विभिन्न आयामों की व्यवस्थित समीक्षा करना तथा यह विश्लेषण करना है कि यह क्षेत्रीय संघर्ष किस प्रकार वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम उत्पन्न कर रहा है। अध्ययन विशेष रूप से ऊर्जा बाज़ार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मानवीय संकट और वैश्विक शक्ति संतुलन पर केंद्रित है।

1.1 शोध की आवश्यकता एवं महत्व : वैश्वीकरण के वर्तमान युग में कोई भी क्षेत्रीय संघर्ष अब पूर्णतः स्थानीय नहीं रहता। पश्चिम एशिया संकट ने यह सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार एक भू-राजनीतिक टकराव तेल आपूर्ति श्रृंखला, वित्तीय बाज़ारों, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे को एक साथ प्रभावित कर सकता है। भारत जैसे ऊर्जा-आयातक देशों के लिए यह विषय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता का बड़ा भाग खाड़ी क्षेत्र से आता है। अतः इस विषय पर अकादमिक अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधार्थियों और नीति-विश्लेषकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

1.2 शोध उद्देश्य :

- पश्चिम एशिया के वर्तमान संघर्षों की पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- वैश्विक तेल एवं गैस बाज़ार पर संकट के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिपिंग एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करना।
- संकट के मानवीय एवं सामाजिक आयामों का विश्लेषण करना।
- वैश्विक भू-राजनीतिक संतुलन तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।

1.3 शोध पद्धति : यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) पर आधारित एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट्स, OCHA, UNRWA, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन तथा ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा जून 2026 तक प्रकाशित रिपोर्टों एवं आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

2. पश्चिम एशिया संकट की पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति

2.1 गाज़ा संघर्ष एवं युद्धविराम की स्थिति : अक्टूबर 2023 में प्रारंभ हुआ इज़राइल-हमास संघर्ष नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के माध्यम से अमेरिका-मध्यस्थ 'व्यापक योजना' (Comprehensive Plan) के अंतर्गत एक औपचारिक युद्धविराम में परिणत हुआ। इस प्रस्ताव के तहत गाज़ा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (International Stabilization Force - ISF) की तैनाती, हमास के निरस्त्रीकरण, इज़राइली सेना की चरणबद्ध वापसी तथा एक पुनर्गठित फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सत्ता हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी। तथापि, 2026 के मध्य तक भी यह प्रक्रिया काफी हद तक अटकी हुई है। हमास द्वारा हथियार सौंपने से इनकार तथा गाज़ा में जारी इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों ने युद्धविराम को अत्यंत नाज़ुक बना दिया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के अनुसार अक्टूबर 2023 से मई 2026 के बीच गाज़ा पट्टी में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों की मृत्यु हुई तथा लाखों घायल हुए, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक जल एवं स्वच्छता अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पश्चिमी तट (West Bank) में भी बसने वालों (Settlers) की हिंसा

तथा इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों में लगातार वृद्धि दर्ज़ की गई है, जिससे हज़ारों फ़िलिस्तीनी शरणार्थी विस्थापित हुए हैं।

2.2 इज़राइल-ईरान युद्ध (फरवरी–अप्रैल 2026) : 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर सैन्य हमले प्रारंभ किए, जिसके परिणामस्वरूप एक पूर्ण-स्तरीय क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्युत्तर में ईरान की क्रांतिकारी रक्षक कोर (IRGC) ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों तथा छोटी नौकाओं के माध्यम से जहाज़ों पर हमले किए, समुद्री खदानें बिछाईं तथा जलडमरूमध्य को अमेरिका, इज़राइल एवं उनके सहयोगियों के लिए 'बंद' घोषित कर दिया। 13 अप्रैल से 29 मई 2026 के बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी की। 8 अप्रैल 2026 को दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा हुई, तथा 17 जून को अमेरिका-ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हुए, किंतु यह संघर्ष को पूर्णतः कूटनीति की ओर स्थानांतरित नहीं कर सका। होर्मुज़ जलडमरूमध्य आज भी तनाव का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

2.3 लेबनान: इज़राइल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष : इज़राइल-ईरान युद्ध के समानांतर, इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच लेबनान में संघर्ष भी तीव्र हुआ, जिसमें इज़राइली सेना लितानी नदी के उत्तर तक आगे बढ़ी। 3 जून 2026 को वाशिंगटन में हुई वार्ता के पश्चात युद्धविराम कार्यान्वयन की घोषणा हुई, जिसके बाद हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई । तथापि, दक्षिणी लेबनान में तोपखाने और रॉकेट हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है, जो यह दर्शाता है कि युद्धविराम ने शत्रुता को समाप्त नहीं बल्कि केवल सीमित किया है।

2.4 यमन, हूती विद्रोही एवं लाल सागर संकट : यमन के हूती विद्रोहियों ने मार्च 2026 में औपचारिक रूप से ईरान-समर्थित संघर्ष में प्रवेश किया तथा लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले फिर से प्रारंभ कर दिए, जिससे अक्टूबर 2025 के युद्धविराम के बाद हुई सीमित प्रगति भी उलट गई। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक शिपिंग कंपनियों—मर्स्क, MSC, CMA CGM तथा हापाग-लॉयड—ने लाल सागर एवं स्वेज़ नहर मार्ग को छोड़कर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर (केप ऑफ़ गुड होप) से होकर लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाया, जिससे परिवहन लागत एवं समय दोनों में भारी वृद्धि हुई।

2.5 इराक़ एवं क्षेत्रीय मिलिशिया की भूमिका : युद्ध के प्रथम माह में ही इराक़, अमेरिकी सेनाओं तथा ईरान-समर्थित मिलिशिया समूहों के बीच टकराव का एक सक्रिय मोर्चा बन गया। ईरान-समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा अमेरिकी प्रतिष्ठानों तथा ऊर्जा अवसंरचना पर दर्जनों ड्रोन एवं गोलाबारी हमले किए गए, जिनके जवाब में अमेरिका ने पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज़ (PMF) के ठिकानों पर लगभग 100 हवाई हमले किए। हाल के महीनों में इराक़ी सरकार पर मिलिशिया के निरस्त्रीकरण हेतु अमेरिकी दबाव बढ़ा है, और कुछ गुटों ने अपने हथियार राज्य को सौंपने की घोषणा भी की है, यद्यपि पूर्ण निरस्त्रीकरण अभी दूर की संभावना प्रतीत होती है।

3. वैश्विक आर्थिक प्रभाव

3.1 वैश्विक तेल बाज़ार पर प्रभाव : अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने इज़राइल-ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न व्यवधान को 'वैश्विक तेल बाज़ार के इतिहास का सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान' और 'ऊर्जा सुरक्षा की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती' के रूप में वर्णित किया है। युद्ध-पूर्व होर्मुज़ जलडमरूमध्य से विश्व के लगभग 20 से 27 प्रतिशत समुद्री कच्चे तेल व्यापार तथा लगभग 20 प्रतिशत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का परिवहन होता था। युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2 मार्च 2026 को लगभग 10 से 13 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज़ हुई, और मार्च के अंत तक यह लगभग 65 प्रतिशत (46 डॉलर प्रति बैरल) तक बढ़ गई—जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक वृद्धि थी। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक तेल उत्पादन में मार्च माह में 10.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की भारी गिरावट दर्ज़ हुई।

यद्यपि युद्धविराम के पश्चात कीमतों में कुछ नरमी आई, फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। विश्व बैंक के अप्रैल

2026 के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2026 में ब्रेंट क्रूड का औसत मूल्य लगभग 86 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है, जो 2027 में आपूर्ति स्थिर होने पर घटकर लगभग 70 डॉलर तक आ सकता है। सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दरकिनार करते हुए क्रमशः यानबू (लाल सागर) तथा फुजैराह (ओमान की खाड़ी) की ओर वैकल्पिक पाइपलाइनों का अधिकतम उपयोग किया, जिससे कुछ हद तक आपूर्ति संकट कम हुआ। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इतिहास की सबसे बड़ी सामरिक तेल भंडार रिलीज़—लगभग 400 मिलियन बैरल—का समन्वय किया।

3.2 प्राकृतिक गैस एवं यूरोपीय ऊर्जा संकट : क़तर से यूरोप को होने वाली LNG आपूर्ति (जो यूरोप की कुल LNG आवश्यकता का लगभग 12 से 14 प्रतिशत है) होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रती थी, अतः क़तरएनर्जी द्वारा 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) की घोषणा ने यूरोपीय ऊर्जा आपूर्ति को सीधे प्रभावित किया। पूर्व से ही निम्न स्तर (लगभग 30 प्रतिशत क्षमता) पर स्थित यूरोपीय गैस भंडार इस संकट से और अधिक दबाव में आ गए, जिससे डच TTF गैस बेंचमार्क मार्च के मध्य तक लगभग दोगुना होकर 60 यूरो प्रति मेगावाट-घंटा से अधिक पहुँच गया। कई विश्लेषकों तथा संस्थाओं ने इसकी तुलना वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उत्पन्न यूरोपीय ऊर्जा संकट से की है। इस संकट ने यूरोप में रूसी यमल LNG के आयात को भी बढ़ावा दिया, जो पूर्व की ऊर्जा-विविधीकरण नीतियों के विपरीत था।

3.3 वैश्विक व्यापार, शिपिंग एवं आपूर्ति श्रृंखला : इतिहास में पहली बार पश्चिम एशिया के दोनों प्रमुख समुद्री गलियारे—स्वेज़ नहर/लाल सागर मार्ग तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य—एक साथ अवरुद्ध हुए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनुसार अप्रैल 2026 तक लगभग 20,000 नाविक तथा 2,000 जहाज़ फारस की खाड़ी क्षेत्र में फँस गए थे। युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम पूर्व की तुलना में चार से पाँच गुना तक बढ़ गए, जिससे परिवहन लागत में भारी वृद्धि हुई। चीन (जो अपने कुल तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत होर्मुज़ जलडमरूमध्य से प्राप्त करता है), जापान (लगभग 70 प्रतिशत) तथा दक्षिण कोरिया जैसी प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ इस संकट से विशेष रूप से प्रभावित हुईं। जापान ने अपने सामरिक तेल भंडार जारी करने की माँग की, जबकि फिलीपींस ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु एक विशेष संकट समिति गठित की।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 'असममित' (Asymmetric) प्रभाव उत्पन्न करता है—ऊर्जा-आयातक देश ऊर्जा-निर्यातक देशों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं, निर्धन देश समृद्ध देशों की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं, और सीमित राजकोषीय संसाधनों वाले देश सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने चेतावनी दी है कि उच्च ऋण-भार तथा सीमित राजकोषीय गुंजाइश वाले विकासशील देशों के लिए यह संकट विशेष रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

3.4 मुद्रास्फीति, खाद्य एवं उर्वरक संकट : होर्मुज़ जलडमरूमध्य से विश्व के लगभग एक-तिहाई उर्वरक शिपमेंट का भी परिवहन होता है। उत्तरी गोलार्ध में बुवाई का मौसम प्रारंभ होते ही इस व्यवधान ने फसल उत्पादन तथा खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका उत्पन्न कर दी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार निम्न-आय वाले विकासशील देशों में खाद्य पदार्थों का हिस्सा कुल उपभोग व्यय का लगभग 43 प्रतिशत होता है (जबकि उभरते बाज़ारों में लगभग 25 प्रतिशत तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 12 प्रतिशत), जिससे खाद्य एवं उर्वरक कीमतों में वृद्धि निर्धन देशों के लिए न केवल एक आर्थिक बल्कि एक सामाजिक-राजनीतिक संकट भी बन जाती है। विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार तेल कीमतों में निरंतर वृद्धि वैश्विक मुद्रास्फीति में लगभग 0.8 प्रतिशत तक की अतिरिक्त वृद्धि कर सकती है।

गाज़ा पट्टी में भी मूल्य वृद्धि अत्यंत गंभीर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार जून 2026 तक स्थानीय

बाज़ार मूल्य अक्टूबर 2023 से पूर्व की तुलना में लगभग 235 प्रतिशत तथा अक्टूबर 2025 के युद्धविराम के बाद की अवधि की तुलना में लगभग 88 प्रतिशत अधिक बने हुए थे, जो यह दर्शाता है कि संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय एवं आर्थिक संकट किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं।

3.5 वैकल्पिक ऊर्जा एवं दीर्घकालिक ऊर्जा नीति पर प्रभाव : दिलचस्प रूप से, इस संकट ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है, क्योंकि सौर एवं पवन ऊर्जा बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम करते हुए विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों से अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण नवीकरणीय ऊर्जा अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है, और यूरोप में अप्रैल 2026 विद्युत वाहन बिक्री के लिहाज़ से अब तक का सबसे मज़बूत महीना रहा।

4. मानवीय संकट एवं इसका वैश्विक आयाम

4.1 गाज़ा में मानवीय स्थिति : संयुक्त राष्ट्र फ़िलिस्तीनी शरणार्थी राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) तथा OCHA की रिपोर्टों के अनुसार गाज़ा पट्टी की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। एक संयुक्त यूरोपीय संघ-संयुक्त राष्ट्र आकलन के अनुसार दो वर्षों के संघर्ष ने गाज़ा के विकास को लगभग 77 वर्ष पीछे धकेल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार 43,000 से अधिक लोग स्थायी रूप से जीवन-परिवर्तनकारी चोटों से ग्रस्त हैं, जबकि पुनर्वास सेवाएँ अत्यंत सीमित हैं। जल एवं स्वच्छता अवसंरचना का लगभग 90 प्रतिशत भाग नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या पेयजल हेतु जल-टैंकरों पर निर्भर है।

मानवीय सहायता के लिए धन की भारी कमी एक अन्य गंभीर चुनौती है। वर्ष 2026 के प्रारंभिक चार महीनों में आवश्यक धनराशि का मात्र 10 प्रतिशत ही सुरक्षित हो सका, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मलबा-हटाने जैसी अनिवार्य सेवाएँ प्रभावित हुई हैं। इसके अतिरिक्त सहायताकर्मियों की सुरक्षा भी एक चिंता का विषय रही है।

4.2 पश्चिमी तट में बढ़ती हिंसा : गाज़ा से इतर, पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) में भी बसने वालों की हिंसा तथा इज़राइली प्रशासनिक कार्रवाइयों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में बसने वालों की हिंसा के कारण घायल फ़िलिस्तीनियों की मासिक औसत संख्या 2024 की तुलना में तीन गुना से अधिक बढ़ चुकी है। हज़ारों फ़िलिस्तीनी शरणार्थी जेनिन, तुलकरम एवं नूर शम्स शरणार्थी शिविरों से विस्थापित हुए हैं—जनवरी 2025 से अब तक यह 1967 के बाद पश्चिमी तट का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा विस्थापन संकट बन चुका है। यूरोपीय संघ ने बसने वालों की हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं, यद्यपि इसका ठोस प्रभाव सीमित रहा है, क्योंकि व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान को पश्चिमी तट की स्थिति से दूर कर दिया है।

4.3 वैश्विक शरणार्थी एवं प्रवासन दबाव : क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण पड़ोसी देशों—जॉर्डन, लेबनान, मिस्र तथा इराक़—पर शरणार्थियों का दबाव बना हुआ है, जिससे इन देशों की पहले से ही सीमित आर्थिक क्षमता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंताओं, यूरोप में प्रवासन नीतियों पर राजनीतिक बहस, तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता तंत्र पर बढ़ते दबाव के रूप में भी इस संकट के परोक्ष प्रभाव देखे जा सकते हैं।

4.4 महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष प्रभाव : संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women) तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि विस्थापन, भीड़भाड़ वाले एवं असुरक्षित रहने की स्थितियों तथा पारिवारिक-सामुदायिक सुरक्षा तंत्र के विघटन के कारण महिलाओं एवं बालिकाओं में लैंगिक-आधारित हिंसा का खतरा काफी बढ़ गया है। साथ ही बाल-विवाह जैसी हानिकारक अनुकूलन रणनीतियों में वृद्धि की भी रिपोर्ट की गई है।

5. भू-राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव

5.1 अमेरिका की भूमिका एवं वैश्विक नेतृत्व पर प्रभाव : इस संकट में अमेरिका की प्रत्यक्ष सैन्य संलिप्तता—विशेष

रूप से ईरान पर हमलों तथा तत्पश्चात नौसैनिक नाकाबंदी के माध्यम से—ने वैश्विक शक्ति संतुलन पर नए प्रश्न खड़े किए हैं। एक ओर अमेरिका ने गाज़ा में 'व्यापक योजना' के माध्यम से एक कूटनीतिक ढाँचा स्थापित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ सैन्य टकराव ने क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता की संभावनाओं को जटिल बना दिया है।

5.2 खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों की स्थिति : सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, कुवैत तथा बहरीन सहित खाड़ी देशों ने संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना तनाव कम करने की नीति अपनाई। तथापि, मई 2026 में ईरान तथा उसके इराक़-स्थित सहयोगी समूहों द्वारा युद्धविराम के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत तथा सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों तथा समुद्री शिपिंग पर हमले जारी रहे, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय तनाव पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। कुछ खाड़ी देशों, जैसे क़तर ने, ईरान से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की माँग भी रखी है।

5.3 चीन एवं रूस की भूमिका : ऊर्जा संकट के दौरान चीन ने अपने विशाल सामरिक तेल भंडार (लगभग 1.4 अरब बैरल, विश्व में सबसे बड़ा) के माध्यम से आपूर्ति के झटकों को अवशोषित करने का प्रयास किया, साथ ही समुद्री तेल आयात को सीमित करते हुए भंडार से निकासी को प्राथमिकता दी। यूरोप द्वारा रूसी यमल LNG के आयात में वृद्धि यह दर्शाती है कि पश्चिम एशिया संकट ने अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप-रूस ऊर्जा संबंधों को भी पुनः आकार देना प्रारंभ कर दिया है, जो यूरोपीय संघ की पूर्व ऊर्जा-विविधीकरण नीति के विपरीत दिशा में एक घटनाक्रम है।

5.4 संयुक्त राष्ट्र एवं बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के माध्यम से गाज़ा के लिए एक 'संक्रमणकालीन शासन प्रशासन' (Board of Peace) तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की स्थापना बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, यद्यपि इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ बनी हुई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के भीतर भी पश्चिमी देशों तथा चीन-रूस के मध्य दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है, जो वैश्विक शासन-तंत्र में गहरे विभाजन को इंगित करता है।

5.5 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन की प्रवृत्ति : विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की 'ग्लोबल वैल्यू चेन्स आउटलुक 2026' रिपोर्ट के अनुसार अब लगभग तीन-चौथाई वैश्विक व्यापार प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (Resilience) में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं, तथा दक्षता-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से हटकर 'अनुकूलनीय नेटवर्क' (Adaptive Networks) की ओर रुझान बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति पश्चिम एशिया संकट सहित हाल के वर्षों की अनेक भू-राजनीतिक घटनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम प्रतीत होती है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव : पश्चिम एशिया का वर्तमान संघर्ष यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि 21वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संघर्ष अब पूर्णतः स्थानीयकृत नहीं रह सकते। गाज़ा, लेबनान, यमन तथा ईरान में समानांतर रूप से चल रहे संघर्षों ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों, मुद्रास्फीति दरों तथा विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा को गहराई से प्रभावित किया है। इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

- ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से होर्मुज़ जलडमरूमध्य तथा लाल सागर जैसे समुद्री चोकपॉइंट्स की भेद्यता (vulnerability) एक बार फिर उजागर हुई है, जिससे विश्व को वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों तथा स्रोतों में विविधीकरण की आवश्यकता महसूस हुई है।
- वैश्विक आर्थिक प्रभाव असममित है—ऊर्जा-आयातक तथा निर्धन देश सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि इसने वैश्विक असमानता को और गहरा करने की आशंका उत्पन्न की है।
- मानवीय संकट, विशेषकर गाज़ा में, वैश्विक मानवाधिकार तथा मानवीय सहायता ढाँचे की सीमाओं को उजागर करता है।

- बहुपक्षीय कूटनीति (जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2803) महत्वपूर्ण प्रगति का माध्यम बन सकती है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी पक्षों की सतत प्रतिबद्धता आवश्यक है।
- यह संकट नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को गति दे सकता है, क्योंकि देश जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना चाहेंगे।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया संकट का समाधान न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय व्यवस्था के लिए भी अनिवार्य है। नीति-निर्माताओं को दीर्घकालिक समाधान हेतु कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही ऊर्जा-आयातक देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

संदर्भ सूची (References) :

1. ACLED. (2026). Middle East Overview: April, June 2026. Armed Conflict Location & Event Data Project. acleddata.com
2. Brookings Institution. (2026). From chokepoint to crisis: The Strait of Hormuz and global oil markets. brookings.edu
3. nternational Monetary Fund. (2026, March 30). How the War in the Middle East Is Affecting Energy, Trade, and Finance. imf.org
4. OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) (2026). Humanitarian Situation Reports, April–June 2026. ochaopt.org.
5. Security Council Report. (2026). The Middle East, including the Palestinian Question - Monthly Forecasts, April 2026. securitycouncilreport.org.
6. UNCTAD. (2026). Strait of Hormuz disruptions: Implications for global trade and development. unctad.org.
7. UNRWA. (2026). Situation Reports on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the Occupied West Bank (207–221). unrwa.org.
8. US Congressional Research Service (Congress.gov). (2026). Iran Conflict and the Strait of Hormuz: Impacts on Oil, Gas, and Other Commodities.
9. World Bank. (2026, April). Commodity Markets Outlook - Strait of Hormuz disruption sends oil prices surging. worldbank.org.
10. World Economic Forum. (2026). Global Value Chains Outlook 2026 & Middle East conflict trade updates. weforum.org.
11. Wikipedia contributors. (2026). 2026 Strait of Hormuz crisis; 2026 Iran war fuel crisis. en.wikipedia.org.
12. मार्च से जून 2006 तक दैनिक जागरण, भास्कर ,हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, टाईम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दू इत्यादि समाचार पत्रों के संपादकीय लेख।

•